नईदुनिया

नेपाल-चीन के बीच पहली अंतरदेशीय बिजली प्रसारण लाइन बनने की उम्मीद

काठमांडू

नेपाल और चीन के बीच पहली अंतरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन बनने की उम्मीद मजबूत हुई है। सरकार द्वारा चिलिमे-केरुङ-जिलोङ 220 केवी अंतरदेशीय प्रसारण लाइन के कार्यान्वयन के लिए चीन को लेटर आफ रिप्लाई भेजने का निर्णय लेने के साथ ही लंबे समय से चर्चा में रही यह परियोजना निर्णायक चरण में पहुंच गई है।

इस निर्णय के साथ नेपाल ने भारत और बांग्लादेश के बाद उत्तरी पड़ोसी चीन के साथ भी बिजली व्यापार की दिशा में रणनीतिक कदम बढ़ाया है। वर्तमान में नेपाल का अंतरदेशीय बिजली व्यापार भारतीय प्रसारण प्रणाली के माध्यम से होता है। ऐसे में चीन के साथ सीधी प्रसारण लाइन जुड़ना ऊर्जा क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। प्रस्तावित प्रसारण लाइन चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सिगात्से स्थित जिलोङ काउंटी से शुरू होगी। जिलोङ नेपाल-चीन सीमा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह प्रसारण लाइन चीन की ओर लगभग 94 किलोमीटर और नेपाल की ओर लगभग 26 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी कुल लंबाई करीब 120 किलोमीटर होगी। यह लाइन रसुवागढ़ी होते हुए रसुवा के चिलिमे हब तक पहुंचेगी। नेपाल-चीन अंतरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजना के प्रमुख कोमलनाथ आत्रेय के अनुसार, दोनों देशों के बीच अंतिम कार्यान्वयन समझौते की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान इस विषय को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अब दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौता होना बाकी है। सरकार का पत्र स्वीकृति प्रक्रिया में है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही समझौता पूरा हो जाएगा। आत्रेय के अनुसार, प्रारंभिक योजना के तहत दोनों देशों को अपने-अपने भूभाग में निर्माण कार्य स्वयं करना था। लेकिन बाद में चीन ने नेपाल वाले हिस्से को भी अनुदान के तहत बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके कारण परियोजना की कार्यान्वयन प्रणाली में बदलाव करना पड़ा। नेपाल लंबे समय से चीन के साथ इस प्रसारण लाइन के निर्माण के लिए औपचारिक पहल करता आ रहा है। सन् 2017 में तत्कालीन उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री कृष्ण बहादुर महरा की चीन यात्रा के दौरान इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर प्रारंभिक सहमति बनी थी। इसके बाद 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान आगे की कार्यविधि तय हुई। 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने जिलोङ/केरुङ-रसुवागढ़ी-चिलिमे 220 केभी प्रसारण लाइन को शीघ्र निर्माण करने पर सहमति जताई। फिर 2025 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान इस परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत शामिल किया गया। बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में शामिल 10 परियोजनाओं में इसे सबसे आगे बढ़ा हुआ प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यही कारण है कि इसे नेपाल में बीआरआई के तहत लागू होने वाली पहली ठोस आधारभूत संरचना परियोजना के रूप में देखा जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

बेलारूस ने अपनी सेना का तेजी से किया विस्तार, नए सैन्य कमांड बनाए

बेलारूस। बेलारुस की सरकार रूस-यूक्रेन युद्ध में सीधे शामिल होने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विपक्षी संगठन यूनाइटेड ट्रांजिशनल कैबिनेट ने इस बारे में एक रिपोर्ट यूक्रेन सरकार को सौंपी है। विपक्ष का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बेलारूस ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जो युद्ध की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में बताया है कि देश ने अपने सैन्य कानूनों में बदलाव किए हैं। इन बदलों के चलते जरूरत पड़ने पर विदेशों में सेना भेजने का रास्ता खुल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेता स्वेतलाना त्सिखानोव्सकाया ने कहा कि यूक्रेन का संघर्ष केवल उसकी आजादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह बेलारूस के लोकतांत्रिक भविष्य से भी जुड़ा है। उनका मानना है कि यूक्रेन की सफलता बेलारूस में राजनीतिक बदलाव की उम्मीदों को मजबूत कर सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेलारूस ने कुछ सालों में अपनी सेना का तेजी से विस्तार किया है। सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, नए सैन्य कमांड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में रिजर्व बल तैयार किए जा रहे हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया गया है और कैदियों को भी सेना में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में दावा है कि बेलारूस में रूसी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है, जबकि रूस के सामरिक परमाणु हथियार और अन्य आधुनिक मिसाइल सिस्टम भी वहां तैनात की हैं, साथ ही रूसी वैगनर ग्रुप के ट्रेंड बेलारूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि, यह सभी दावे बेलारूस के विपक्ष की रिपोर्ट पर आधारित हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

चीन से 24 फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश, प्रधानमंत्री रहमान के बीजिंग दौरे पर लग सकती हैं मोहर

ढाका। बांग्लादेश अपनी वायुसेना की युद्धक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में चीन से 24 अत्याधुनिक जे-10सीई मल्टी-रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया काफी तेज है। इस सैन्य समझौते पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की आगामी चीन यात्रा के दौरान बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री रहमान इसी सप्ताह चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां 26 जून को उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी मोर्चे पर होने वाली रणनीतिक हलचल भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान की वायु सेना भी पहले से ही इसी चीनी फाइटर जेट का संचालन कर रही है। ढाका और बीजिंग के बीच बढ़ता यह रक्षा सहयोग दोनों देशों के गहरे होते रणनीतिक रिश्तों को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार आगामी अगस्त महीने तक इस फाइटर जेट सौदे को पूरी तरह फाइनल करने की उम्मीद जाहिर कर रही है।

चर्चा का विषय बनीं अमेरिका की अनोखी डार्क सीक्रेट सेवा

वाशिंगटन। अमेरिका में एक ऐसी अनोखी सेवा चर्चा का विषय बनी हुई है, जो अंतिम संस्कार को रहस्य और जिज्ञासा से भर देने का दावा करती है। इस सेवा का नाम डार्क सीक्रेट बताया जा रहा है। इस सेवा के तहत एक रहस्यमयी महिला अंतिम संस्कार में पहुंचती है, कुछ देर तक चुपचाप शोक व्यक्त करती है। इसके बाद महिला बिना किसी से बात किए वहां से चली जाती है। उसका उद्देश्य केवल एक ऐसा सवाल छोड़ जाना होता है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। जानकारी के अनुसार, इस सेवा को लेने वाले लोग एक निश्चित शुल्क देकर उस महिला को अंतिम संस्कार में बुलाते हैं। महिला पूरी तरह काले परिधान में, हाथ में छाता लिए और बेहद गंभीर भाव-भंगिमा के साथ समारोह में पहुंचती है। वह किसी से बातचीत नहीं करती, न ही अपनी पहचान बताती है। पूरे समय वह दूर खड़ी होकर मृतक को श्रद्धांजलि देती हुई दिखाई देती है और फिर अचानक वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद उपस्थित लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो जाती है कि वह कौन थी और मृतक से उसका क्या संबंध था। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य अंतिम संस्कार को एक यादगार और रहस्यमय अनुभव में बदलना बताया जाता है। आयोजकों का दावा है कि इससे लोगों के मन में मृतक को लेकर एक अनकही कहानी और जिज्ञासा बनी रहती है। कई लोग इसे अंतिम विदाई में भावनात्मक और नाटकीय तत्व जोड़ने का नया तरीका मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल ध्यान आकर्षित करने की कोशिश बताते हैं।

ईरान को कौन देगा 300 अरब डालर रुबियो की खाड़ी यात्रा पर टिकी निगाहें

तेहरान

मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने वाले प्रस्तावित समझौते की सबसे बड़ी और जटिल शर्त ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डालर के फंड की व्यवस्था है। यह भारी-भरकम राशि ईरान को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त मानी जा रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस रकम का भुगतान कौन करेगा। इस्लामाबाद एमओयू नामक दस्तावेज में यह लिखा है कि अमेरिका अपने खाड़ी के साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डालर की एक ठोस योजना तैयार करेगा, और इस योजना को अंतिम समझौते के साथ 60 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। इस फंड के अलावा, अमेरिका सभी आवश्यक लाइसेंस, छूट और अनुमतियां भी देगा ताकि पैसे के लेन-देन में कोई रुकावट न आए। साथ ही, अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान पर लगी सभी प्रकार की पाबंदियां हटा ली जाएंगी और उसे तुरंत तेल बेचने की छूट मिल जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान को ये सब पाने के लिए 60 दिनों के भीतर शर्तों का पालन करना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स का एक भी डालर ईरान को नहीं जाएगा। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि ईरान को इतनी बड़ी रकम देगा कौन

इस डील को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका इसके पैसे अपने अमीर खाड़ी देशों से वसूलेगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये वही खाड़ी देश हैं, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे स्थित हैं और जिन पर युद्ध के दौरान ईरान ने हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। युद्ध से तबाह हो चुके ईरान को इस फंड की सख्त जरूरत है, लेकिन खाड़ी देश अभी इस भुगतान के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले हफ्ते इस फंड पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह कहकर बात टाल दी कि पहले विश्वास बहाल करना होगा। उनका मानना है कि ईरान के हमलों के बाद रिश्ते सुधारने की बातचीत जरूरी है, उसके बाद ही आर्थिक सहयोग और निवेश की बात हो सकती है। सऊदी अरब इस समय अपनी घरेलू परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पहले ही ईरान से युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की थी, हालांकि समझौते से पहले उसका रुख कुछ नरम हुआ था। यूएई युद्ध से पहले ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी था, बावजूद इसके उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा था, जिससे उसके भीतर विश्वास की कमी है। इन तमाम सवालों के बीच, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो तीन दिन के खाड़ी देशों के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे यूएई, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद अपने साझेदार देशों में यह विश्वास जगाना है कि तेहरान के साथ अमेरिका की डील से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें इन देशों को यह स्पष्ट करना होगा कि 300 अरब डालर का निवेश पैकेज आएगा कहां से और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के लिए तो यह एक डील है, लेकिन खाड़ी देशों के लिए यह उनके अस्तित्व और सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि तेहरान यह रकम मिलने के बाद खुद को आर्थिक रूप से खड़ा तो करेगा, लेकिन उनकी सैन्य और क्षेत्रीय प्रभाव भी मजबूत होगा। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी जैसे देश खाड़ी की सुरक्षा में अहम योगदान निभाते हैं, ऐसे में ईरान का मजबूत होना उनके लिए सिरदर्द बन सकता है। खाड़ी देशों को इस बात का डर है कि पैसा ईरान के हथियारों और प्राक्सी समूहों पर खर्च न हो जाए। इसलिए उन्हें मजबूत गारंटी चाहिए। जब तक उन्हें यह विश्वास मिल नहीं जाता, तब तक वे शायद ही अपना कोष ईरान के लिए खोलें। समझौते में ईरान के फ्रोजन असेट्स को पूरी तरह उपलब्ध कराने का वादा है, जिसके लिए जेडी वेंस ने कतर और जेयर्ड कुश्नर द्वारा निकाले गए दिलचस्प समाधान का जिक्र किया। अमेरिका और कतर इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। वेंस के मुताबिक, अगर पैसे छोड़े गए तो वे ईरानी लोगों को खाना खिलाने और अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने में लगाए जाएंगे, जिससे ईरान अमेरिका से सोयाबीन, मक्का और गेहूं खरीद सकेगा। हालांकि, तेहरान के केंद्रीय बैंक ने इस दावे से इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है।

ईरान ने कहा- अब होर्मुज पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं चलेगा

तेहरान

अमेरिका के साथ हालिया वार्ता के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक टेलीफोनिक हाटलाइन स्थापित करने का फैसला किया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने स्विट्जरलैंड यात्रा से वापस आने के बाद यह बात कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि होर्मुज अब पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं लौट पाएगा और इसका प्रबंधन ईरानी प्रशासन के ही जिम्मे रहेगा। गलिबाफ ने कहा कि सबको इस बात का पता होना चाहिए कि युद्ध से पहले होर्मुज से आवाजाही जिस तरीके से चल रही थी, अब वैसे नहीं चल पाएगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ईरान अमेरिका पर ना कभी विश्वास करता था और ना ही आगे कर पाएगा। वार्ता में ईरान और अमेरिका एक कोआर्डिनेशन मकैनिज्म बनाने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत कोई भी जहाज हाटलाइन के जरिए संपर्क कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने लेबनान में संघर्ष खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा कि नया प्रकोष्ठ ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते की पहली बड़ी परीक्षा होगी।

यूएस को धोखेबाज बताया और हाटलाइन स्थापित करने का ऐलान किया

अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक के अनुसार, बर्गेनस्टाक में हुई बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान के हालिया बयानों से पैदा हुई उलझन, नौवहन की आज़ादी सुनिश्चित करने के उपाय और लेबनान में तनाव बढ़ने से रोकने के तरीके शामिल थे। राजनयिक ने कहा कि बातचीत करने वालों ने भविष्य में संभावित परमाणु समझौते के पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि आने वाले दिनों में तकनीकी बातचीत जारी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के तेहरान लौटने से पहले बातचीत का पहला दौर लगभग 18 घंटे तक चला। बैठकों के अगले दौर के लिए हालांकि कोई समय-सारणी घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस सप्ताह बातचीत जारी रखेंगे। वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री आवाजाही को शामिल करते हुए एक व्यापक समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता लाना है।

भूकंप के बाद 200 मीटर पीछे खिसका समुद्र, तटीय इलाकों का नक्शा बदला

मिंडानाओ। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से मिंडानाओ में 8 जून 2026 को आए भीषण भूकंप के बाद एक असाधारण प्राकृतिक घटना देखने को मिली, जहां समुद्र का पानी अचानक लगभग 200 मीटर पीछे हट गया। इस हैरतअंगेज बदलाव ने तटीय इलाकों का पूरा नक्शा बदल दिया और स्थानीय लोगों के साथ-साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के दो दिन बाद जब लोग समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि जहां कुछ दिन पहले तक नावें तैरती थीं, वहां अब सूखी जमीन दिखाई दे रही है। समुद्र के पीछे हटने से मूंगे की चट्टानें, समुद्री घास और अन्य समुद्री संरचनाएं खुलकर सामने आ गईं, जिससे क्षेत्र का पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। इस असामान्य बदलाव ने गहरे पानी वाले क्षेत्रों को अकल्पनीय रूप से उजागर कर दिया, जिससे लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए थे। वैज्ञानिकों ने इस घटना को किसी रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि एक सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है, जिसे तटीय उत्थान कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह के नीचे जमा अत्यधिक दबाव अचानक मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन और समुद्र तल का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है।

जेडी वेंस ने स्पष्ट कहा-भारत किसी भी हाल में नहीं मानेगा

वाशिंगटन

अमेरिकी राजनीति में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के भीतर की कहानियों को बयां करने वाली एक नई किताब रेजीम चेंज में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस किताब में बताया गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बार यूक्रेन युद्ध में भारतीय सैनिकों को तैनात करने का एक विवादास्पद प्लान तैयार किया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इसका प्रस्ताव भी रखा, लेकिन ट्रंप ने इसे सुनते ही सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा था कि भारत इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, भले ही उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध बेहद शानदार क्यों न हों। किताब में ओवल आफिस की एक बेहद गोपनीय बैठक का जिक्र है, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के महज 10 दिन बाद, 30 जनवरी 2025 को बुलाई गई थी। इस हाई-लेवल बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुझाव दिया कि यूक्रेन में सीजफायर की निगरानी के लिए भारत या सऊदी अरब के सैनिकों को शांति सैनिक बनाकर तैनात किया जाना चाहिए। हालांकि, ट्रंप ने वेंस की इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। किताब के मुताबिक, ट्रंप ने योजना सुनकर बेबाकी से कहा, भारतीय ऐसा नहीं करेंगे। वे इसके लिए कभी भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने माना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और प्रधानमंत्री मोदी मुझे बहुत पसंद करते हैं और वे यहां आना चाहते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद ट्रंप ने फिर कहा, भारतीय ऐसी चीज के लिए कभी मानेंगे।

ट्रंप ने आगे स्पष्ट किया कि अगर ब्रिटेन या फ्रांस अपने सैनिकों को वहां भेजना चाहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अमेरिका पर इसका कोई वित्तीय या सैन्य बोझ न पड़े। दरअसल, यह पूरी बैठक ट्रंप के विशेष दूत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलाग ने बुलाई थी। उन्होंने ऐन अमेरिका फर्स्ट प्लान: ट्रम्प्स हिस्टोरिक पीस डील फार रशिया-यूक्रेन वार नाम से एक ड्राफ्ट पेश किया था।

इस प्लान के तहत अमेरिका, यूक्रेन की जमीन पर रूस के कब्जे को आधिकारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन यूक्रेन भी इसे वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा। युद्ध रोकने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों के सैनिकों को जमीन पर तैनात करने का सुझाव था।

हालांकि, वेंस ने इस प्लान पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि नाटो देशों के सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करना रूस को सीधे उकसाने जैसा होगा। इससे तनाव इतना बढ़ सकता है कि अमेरिका भी सीधे तौर पर इस युद्ध में घिसट जाएगा। इसी वजह से वेंस ने यूरोप से बाहर के देशों जैसे भारत और सऊदी अरब का नाम सुझाया था, जिसे ट्रंप ने यह कहकर खारिज कर दिया कि भारत ऐसी किसी भी योजना के लिए सहमत नहीं होगा और न ही इसका वित्तीय बोझ उठाएगा।

पीएम स्टार्मर के इस्तीफे का वैश्विक राजनीति पर होगा असर, ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति

लंदन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे ने न केवल ब्रिटिश राजनीति में हलचल पैदा की है, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। लेबर पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से उनके हटने के बाद ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका असर वैश्विक कूटनीति, व्यापारिक संबंधों और यूरोपीय राजनीति पर पड़ सकता है।

इस्तीफा देने के साथ ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार्मर ने कहा कि लेबर पार्टी अब उन्हें अगले चुनाव में नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं मानती। उन्होंने देशहित को सर्वोपरि बताते हुए पद छोड़ने का निर्णय लिया और नए नेता को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। हाल के महीनों में पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा था। कई सांसदों और नेताओं ने उनकी नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाए थे। स्थानीय चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने और लोकप्रियता में गिरावट ने भी उनके ऊपर दबाव बढ़ाया। यहां बताते चलें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चयन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता। संसद में बहुमत रखने वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए लेबर पार्टी के नए नेता का चुनाव ही ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री का रास्ता तय करेगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जुलाई में नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी और मध्य जुलाई तक नए नेता के चयन की संभावना जताई जा रही है।

मेयर बर्नहैम मजबूत दावेदार

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम को इस समय सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उन्हें पार्टी के विभिन्न गुटों का समर्थन मिलने की चर्चा है। इसके अलावा एंजेला रेनर, यवेट कूपर और वेस स्ट्रीटिंग जैसे नेताओं के नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं।

भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंध होंगे प्रभावित

विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन का असर भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों, यूरोप के साथ ब्रिटेन के रिश्तों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ सकता है। विशेष रूप से ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को पुनर्संतुलित करने की प्रक्रिया पर नए नेतृत्व की नीति महत्वपूर्ण साबित होगी। हालांकि विभिन्न विवादों और राजनीतिक दबावों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति या नेता के संबंध में लगाए गए आरोपों अथवा नामों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि के बिना उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।